



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2013/भाद्र 28, 1935

No. 207]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2013/BHADRA 28, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितंबर, 2013

मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत

विषय : चीन जन.गण., ई यू और यू एस ए के मूल के या वहां से निर्यातित मार्फोलिन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मध्यावधि समीक्षा (एम टी आर) जांच की शुरुआत ।

सं. 15/5/2013—डीजीएडी :—सं. यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने 5 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं० 14/41/2010—डी जी ए डी के तहत अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए और चीन जन.गण., ई यू और यू एस ए (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित “मार्फोलिन” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की और केन्द्र सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2012 की अधिसूचना सं० 10/2012—सी०शु० के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. मै० नोसिल लि० ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया है । उन्होंने दावा किया है कि जो परिस्थितियां मूल जांच की जांच अवधि के दौरान विद्यमान थीं उनमें भारी परिवर्तन हो गया है जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की आगे जरूरत नहीं है ।

विचाराधीन उत्पाद :

3. मूल जांच की भांति वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और यू एस ए के मूल का या वहां से निर्यातित “मार्फोलिन” है । अतः उत्पाद का क्षेत्र वही है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया था । मार्फोलिन अत्यंत बहुपयोगी रसायन है और इसका उपयोग रबड़ उद्योग में एक रसायन मध्यवर्ती, क्षरण नियंत्रण में और कई औषधियों के संश्लेषण में किया जाता है । इसका प्रयोग फसल संरक्षण एजेंटों, रंजकों तथा आप्टीकल ब्राइटनरों के लिए भी किया

जाता है। मार्फोलिन रेजिनो, रंजकों और मोम सहित कई प्रकार की कार्बनिक सामग्री के लिए एक सॉल्वेंट है। इसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जा सकता है। मार्फोलिन का उपयोग 5 प्रतिशत तक के सांद्रणों (सौंदर्य प्रसाधन संघटक) पर प्रसाधन एवं सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों में किया जाता है। इसका प्रयोग कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खाद्य अभिवर्धक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। मार्फोलिन का उपयोग रबड़ एक्सीलरेटर्स के लिए मध्यवर्तियों और स्टीम बॉयलर प्रणालियों में क्षरण निषेधक के रूप में किया जाता है। डिटरजेंट तैयारियों में इसका उपयोग आप्टीकल ब्रायटनर्स के लिए किया जाता है। मार्फोलिन व्युत्पत्तियों का उपयोग रबड़ वल्कनीकरण, स्थिरीकरण और विशेष हाई स्पीड टायरों के विनिर्माण में किया जाता है। मार्फोलिन रबड़ प्रोसेसिंग के दौरान निर्गत हो सकता है। मार्फोलिन में जल के समान बहुपयोगिता होती है। एन मिथाइल मार्फोलिन और एन-इथाइल मार्फोलिन जैसी मार्फोलिन व्युत्पत्तियों का प्रयोग पोलीयूरेथेन फोमों को उत्पादन हेतु उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। मार्फोलिन व्युत्पत्तियों का उपयोग एनालजेसिक और लोकल एनेस्थेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोटिक्स के रूप में तथा घनत्व में प्लेग नियंत्रण में भी किया जाता है। मार्फोलिन का प्रयोग कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खाद्य अभिवर्धक अनुप्रयोगों में किया जाता है। मार्फोलिन का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन उद्योग द्वारा भी किया जाता है। यह उत्पाद सीमाशुल्क वर्गीकरण 29333917 के अंतर्गत आता है। अतः यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

समीक्षा के आधार

4. मध्यावधि समीक्षा के लिए वर्तमान आवेदन निम्नलिखित आधारों पर किया गया है :-
 - क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत में भारी वृद्धि।
 - ख. घरेलू उद्योग द्वारा अत्यंत उच्च कीमत पर निर्यात किए जा रहे हैं।
 - ग. आयातों की पहुंच कीमत क्षति रहित कीमत से अधिक है जिससे नकारात्मक क्षति मार्जिन हुआ है।
 - घ. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षति रहित कीमत से काफी अधिक है।
 - ड. क्षति मार्जिन में परिवर्तन की समीक्षा अपेक्षित है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की निश्चित मात्रा लागू हो रही है।

जांच की शुरुआत

5. नियम 23 (1 क) में मध्यावधि समीक्षा का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। 1 मार्च, 2011 क सी.शु. अधिसूचना सं० 15/2011 के तहत यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली का नियम 23 निम्नानुसार है :

(1) अधिनियम की धारा 9 क के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए उस अवधि तक और उस सीमा तक लागू रहेगा।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां अपेक्षित हो, अपनी खुद की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर जो ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद उचित समयावधि बीत जाती है, किसी पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेगा और ऐसी समीक्षा के उपरांत निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में उसकी समाप्ति हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करेगा जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त या परिवर्तित कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है।

(1 ख) उप नियम (1) या (1क) में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

6. प्राधिकारी के समक्ष उपर्युक्त आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू करना प्रथमदृष्टया उचित समझते हैं।

शामिल देश

7. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन.गण., ई यू और यू एस ए हैं।

प्रक्रिया:

आवेदक द्वारा लागू उपाय की समीक्षा को आवश्यक बताते हुए परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए प्रदान की गई सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी अब यह मानते हैं कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित 5 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं० 14/41/2010-डी जी ए डी के तहत अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों और 24 जनवरी, 2012 की अधिसूचना सं० 10/2012-सी.शु. के तहत केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू करना उचित है और प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 (क) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा जांच शुरू

करते हैं। इस समीक्षा में 5 दिसंबर, 2011 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. 14/41/2010—डी जी ए डी के सभी पहलू तथा 24 जनवरी, 2012 की अधिसूचना 10/2012—सी.शु. के तहत केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क शामिल होगा।

जांच अवधि

9. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में वर्ष 2009—10, 2010—11, 2011—12 की अवधि और जांच अवधि (2012—13) शामिल होगी। प्राधिकारी संभावना के विश्लेषण हेतु जांचोत्तर अवधि से संबंधित आंकड़ों की जांच भी कर सकते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

10. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावासों/उच्चायोगों के जरिए उनकी सरकारों, से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग,

कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

11. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अनुरोध कर सकता है।

समय सीमा

12. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

13. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली का अपना उत्तर दायर करें तथा इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिन के भीतर पाटनरोधी उपाय जारी रखने या अन्यथा की जरूरत के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे (क) गोपनीय रूप में (शीर्षक, विषय सूची, प्रश्न संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए।

15. किसी चित्रांकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतरण की पांच (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण प्रत्येक की पांच (5) प्रस्तुत की जानी चाहिए।

16. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि यह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

17. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

18. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

19. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

20. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

21. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES****NOTIFICATION**

New Delhi, 18th September, 2013

Initiation of Mid-term Review Investigation

Subject: Initiation of Mid-term Review (MTR) investigation in respect of the anti-dumping duties imposed on the imports of Morpholine, originating in or exported from China PR, EU and USA.

No. 15/5/2013-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), notified its final findings vide Notification No. 14/41/2010-DGAD dated 5th December, 2011 and recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of “Morpholine” (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, EU and USA (hereinafter referred to as subject countries) and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 10/2012-Customs dated 24th January, 2012.

2. M/s NOCIL Ltd has submitted an application requesting for initiation of a review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the subject countries in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. They have claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation where the existing antidumping duties are no longer warranted.

Product under Consideration :

3. The product under consideration in the present mid-term review investigation, as in the original investigation, is ‘Morpholine’, originating in or exported from China PR, European Union and USA. The product scope therefore is the same as that defined in the original investigation. Morpholine is an extremely versatile chemical and is used as a chemical intermediate in the rubber industry, in corrosion control, and in the synthesis of a large number of drugs. It is also used for crop protection agents, dyes and optical brighteners. Morpholine is a solvent for a large variety of organic materials, including resins, dyes and waxes. It can be used as a catalyst. Morpholine is used in the in toiletry and cosmetic products at concentrations up to 5% (Cosmetic Ingredient). It can be use for/ in the several direct and indirect food additive applications. Morpholine is used as intermediates for rubber accelerators and as corrosion inhibitor in steam boiler systems. It is used for optical brighteners in detergent formulations. Morpholine derivatives are used in rubber vulcanization, stabilization and the manufacture of special high-speed tyres. Morpholine may be released during rubber processing. Morpholine has volatility similar to water. Morpholine derivatives such as Nmethylmorpholine and N-ethylmorpholine are used as Catalysts for the production of polyurethane foams.

Morpholine derivatives are also used as analgesics and local anesthetics, antibiotics, antimycotics and for plaque control in dentistry. Morpholine is used in several direct and indirect food additive applications. Morpholine is used by the cosmetic industry also. The product falls under customs classification 29333917. Thus, the Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Grounds for Review:

4. The present application for MTR has been made on the following grounds:
 - a. Significant increase in import price of the subject goods from the subject countries.
 - b. Exports being made by domestic industry at significantly higher prices.
 - c. Landed price of imports are above non-injurious price leading to negative injury margin.
 - d. Selling price of the domestic industry is significantly higher than the non-injurious price
 - e. Change in injury margin requires review as the PUC is attracting fixed quantum of ADD.

Initiation:

5. Rule 23 (1A) lays down the scope of a Mid-Term Review. Rule 23 of the AD Rules as amended vide Customs Notification No. 15/2011 dated 1st March 2011 reads as follows:

“(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any antidumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”

6. On the basis of information made available by the aforementioned Applicant before the Authority, the Authority considers it prima facie appropriate to initiate a mid-term review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Countries involved:

7. The countries involved in the present investigation are China PR, EU and USA.

Procedure:

8. Having regard to the information provided by the Applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that it is appropriate to initiate a mid-term review of the final findings notified vide Notification No. 14/41/2010-DGAD dated 5th December, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government vide Notification 10/2012-Customs dated 24th January, 2012 and the Authority hereby initiates an investigation in accordance with the provisions of Section 9(A) of Customs

Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the the Rules supra to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties. The review will cover all aspects of the earlier Notification No. 14/41/2010-DGAD dated 5th December, 2011 and the definitive duties imposed by the Central Government vide Notification 10/2012-Customs dated 24th January, 2012 .

Period of Investigation (POI)

9. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2012 to 31st March, 2013. The injury investigation period will however cover the periods 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI (2012-13). The authority may also examine the data pertaining to the post-POI period data for likelihood analysis.

Submission of Information:

10. The exporters in subject countries, their Governments through their Embassies/High Commissions in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address :

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi -110011.**

11. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit

12. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

13. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic Industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

14. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

15. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

16. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

17. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

18. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

19. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file:

20. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

21. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority